

फा. सं. 7/24/2026-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 30.09.2026

जांच शुरुआत अधिसूचना

सेतु मामला आईडी - AD/SSR/011/2026

विषय चीन पीआर, जापान और कोरिया आरपी में उद्भूत या निर्यात किए गए टोल्यूनि डाई-आइसोसाइनेट (टीडीआई) के आयात से संबंधित सूर्यास्त समीक्षा पाटनरोधीजांच की शुरुआत।

1. फा. सं. 7/24/2026-डीजीटीआर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, समय-समय पर यथा संशोधित (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और सीमा शुल्क टैरिफ (डंप की गई वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह और क्षति के निर्धारण के लिए) नियम, 1995 के संबंध में, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित), गुजरात नर्मदा घाटी उर्वरक और रसायन लिमिटेड (इसके बाद 'आवेदक' या 'घरेलू उद्योग' के रूप में संदर्भित) ने एक आवेदन दायर किया है नामित प्राधिकारी (इसके बाद 'प्राधिकरण' के रूप में संदर्भित) के सामने, टोल्यूनि डी-आइसोसाइनेट (टीडीआई) (इसके बाद 'विचाराधीन उत्पाद', 'पीयूसी' या 'विषय सामान' के रूप में संदर्भित) के आयात पर पाटनरोधीशुल्क की सूर्यास्त समीक्षा जांच शुरू करने के लिए, चीन पीआर, जापान और कोरिया आरपी (इसके बाद 'विषय देशों' के रूप में संदर्भित) में उत्पन्न या निर्यात किया गया।
2. अधिनियम की धारा 9 ए (5) के संदर्भ में, लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि पहले रद्द नहीं किया जाता है, इस तरह के अधिरोपण की तारीख से पांच साल की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा। प्राधिकरण को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर समीक्षा करने की आवश्यकता है कि

क्या शुल्क की समाप्ति से डंपिंग और क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

क. पिछली जांच की पृष्ठभूमि

3. संबंधित देशों से संबंधित वस्तुओं के आयात से संबंधित मूल पाटनरोधी जांच प्राधिकरण द्वारा 5 अक्टूबर 2016 को शुरू की गई थी। प्रारंभिक निष्कर्ष अधिसूचना संख्या 14/36/2016-डीजीएडी दिनांक 28 मार्च 2017 के माध्यम से जारी किए गए थे, जिसमें अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 25/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 5 जून 2017 के माध्यम से लगाया गया था। प्राधिकरण ने 13 दिसंबर 2017 को अंतिम निष्कर्ष जारी किए, जिसमें प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि की गई और पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 3/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 23 जनवरी 2018 के माध्यम से पांच साल की अवधि के लिए लगाया गया था।
4. इसके बाद, प्राधिकरण ने अधिसूचना एफ. संख्या 7/26/2021-डीजीटीआर दिनांक 27 अगस्त 2021 के माध्यम से पहली सूर्यास्त समीक्षा जांच शुरू की। प्राधिकरण ने 24 जून 2022 को अंतिम निष्कर्ष जारी किए और पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश की। इसे स्वीकार कर लिया गया और वित्त मंत्रालय द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 28/2022-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 21 सितंबर 2022 के माध्यम से शुल्क जारी रखा गया। उक्त शुल्क 20 सितंबर 2027 तक लागू है, जब तक कि पहले रद्द न किया गया हो।

ख. विचाराधीन उत्पाद

5. वर्तमान आवेदन एक सूर्यास्त समीक्षा जांच होने के नाते, विचाराधीन उत्पाद मूल जांच में परिभाषित के रूप में ही रहता है, जो इस प्रकार है:

"वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 'टोल्युनि डी-आइसोसाइनेट (टीडीआई)' है जिसमें आइसोमर सामग्री 80:20 के अनुपात में है। टोल्युनि डा-आइसोसाइनेट (टीडीआई) एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र $CH_3C_6H_3(एनसीओ)_2$ है। छह संभावित आइसोमर्स में से दो व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण हैं: 2,4-टीडीआई (सीएस: 584-84-9) और 2,6-टीडीआई (सीएस: 91-08-7)। 2,4-टीडीआई का उत्पादन शुद्ध

अवस्था में किया जाता है, लेकिन टीडीआई को अक्सर क्रमशः 2,4 और 2,6 आइसोमर्स के 80/20 और 65/35 मिश्रण के रूप में विपणन किया जाता है। वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद टीडीआई से संबंधित है जिसमें आइसोमर सामग्री (80:20) के अनुपात में है। अन्य सभी ग्रेड विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं।

उत्पाद को कोड 2929 10 20 के तहत अध्याय शीर्षक 29 के तहत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

6. विषय वस्तुओं का उपयोग लचीले पॉलीयूरेथेन फोम के उत्पादन में किया जाता है, जो फर्नीचर कुशन, औद्योगिक गास्केट, सुरक्षात्मक पैड, ऑटोमोबाइल सीटों और अस्तर और पैकेजिंग में आवेदन पाता है। विचाराधीन उत्पाद के लिए वर्तमान जांच में विचार की गई माप की इकाई मीट्रिक टन (एमटी) है।
7. आवेदक ने उत्पाद नियंत्रण संख्या ("पीसीएन") पद्धति का प्रस्ताव नहीं दिया है। सभी इच्छुक पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे पीयूसी और पीसीएन पद्धति के दायरे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें, यदि आवश्यक है, तो सूचना पत्रों के प्रसारण की तारीख से 15 दिनों के भीतर, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, आवेदन का गैर-गोपनीय संस्करण और संबंधित प्रश्नावली शामिल है, ज्ञात इच्छुक पार्टियों और विषय देश/देशों के राजनयिक प्रतिनिधि (प्रतिनिधिओं) को।

ग. समान वस्तु

8. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और विषय देशों से निर्यात किए गए उत्पाद के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। दोनों तकनीकी विशिष्टताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन, और टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं; वे तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। मूल जांच में प्राधिकरण द्वारा समान लेख के मुद्दे की भी जांच की गई थी। तदनुसार, वर्तमान सूर्यास्त समीक्षा के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद को विषय देशों में उत्पादित और आयातित उत्पाद के लिए 'समान वस्तु' के रूप में माना जाता है।

घ. घरेलू उद्योग और स्थिति

9. आवेदन गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है, जो भारत में विषय वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक ने प्रमाणित किया है कि उसने विषय देशों से विषय वस्तुओं का आयात नहीं किया है और यह विषय देशों में विषय वस्तुओं के किसी भी उत्पादक या निर्यातक या भारत में विषय वस्तुओं के किसी भी आयातक से संबंधित नहीं है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर, प्राधिकरण संतुष्ट है कि आवेदक नियमों के नियम 2 (बी) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग का गठन करता है और यह आवेदन 'घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से' किया गया है। आवेदन नियम 5(3) के संदर्भ में खड़े होने की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है, भले ही नियम 5(3) की आवश्यकताएं सूर्यास्त समीक्षा जांच पर लागू नहीं होती हैं।

ड. संबद्ध देश

10. वर्तमान जांच में विषय देश चीन पीआर, जापान और कोरिया आरपी हैं, जो मूल जांच और पहली सूर्यास्त समीक्षा जांच में विषय देशों के समान हैं।

च. जांच की अवधि

11. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 (12 महीने) तक है। क्षति परीक्षा की अवधि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 और जांच की अवधि को कवर करती है।

छ. कथित पाटन का आधार

1. चीन पीआर के लिए सामान्य मूल्य

12. आवेदक ने दावा किया है कि चीन पीआर को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और चीनी उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि नियमों के अनुलग्नक-1 के पैरा 8 (3) के संदर्भ में विषय वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल होती है। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि वह एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य पर विश्वसनीय जानकारी प्राप्त नहीं कर सका। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि भारत सहित अन्य देशों के लिए तीसरे देश से बाजार अर्थव्यवस्था की कीमत को अपनाया नहीं

जा सकता है, क्योंकि यूरोपीय संघ और सऊदी अरब से आयात को प्राधिकरण द्वारा उन देशों के संबंध में हाल ही में संपन्न सूर्यास्त समीक्षा जांच में डंप की गई कीमतों पर पाया गया है। इसलिए, आवेदक ने नियमों के अनुलग्नक-1 के पैरा 7 के संदर्भ में भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत के आधार पर चीन पीआर के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है, भारत में उत्पादन की लागत को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और उचित लाभ के लिए विधिवत समायोजित किया गया है। शुरुआत के प्रयोजन के लिए, चीन पीआर को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना गया है, जो नियमों के अनुलग्नक-1 के पैरा 8 के अनुसार संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा खंडन के अधीन है, और सामान्य मूल्य का निर्माण नियमों के अनुलग्नक-1 के पैरा 7 के अनुसार किया गया है।

ii. जापान और कोरिया आरपी के लिए सामान्य मूल्य

13. प्राधिकरण नोट करता है कि अधिनियम की धारा 9 ए (1) (सी) निर्यात करने वाले देश में खपत के लिए समान वस्तु के लिए व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में तुलनीय मूल्य निर्दिष्ट करती है और, जहां ऐसी कीमत उपलब्ध नहीं है, निर्यातक देश से एक उपयुक्त तीसरे देश में निर्यात किए जाने पर समान वस्तु का एक तुलनीय प्रतिनिधि मूल्य या प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत और मुनाफे के लिए उचित परिवर्धन के साथ मूल देश में उत्पादन की लागत। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि वह जापान और कोरिया आरपी में विषय वस्तुओं के घरेलू बिक्री मूल्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ था। तदनुसार, आवेदक ने सामान्य मूल्य निर्धारित करने के उद्देश्य से केमएनालिस्ट वेबसाइट पर प्रकाशित मूल्य जानकारी पर भरोसा किया है। उक्त वेबसाइट एशिया-प्रशांत क्षेत्र में प्रचलित विषय वस्तुओं की कीमतों की रिपोर्ट करती है। आवेदक ने संबंधित मूल देशों में विषय वस्तुओं के उत्पादन की लागत का अनुमान प्रस्तुत करके उक्त जानकारी को भी पूरक किया है।
14. प्राधिकरण नोट करता है कि आवेदक द्वारा प्रदान की गई केमएनालिस्ट मूल्य जानकारी जांच की अवधि का केवल एक चौथाई हिस्सा कवर करती है और यह स्पष्ट नहीं करती है कि ऐसी कीमतें देश में खपत की कीमतें हैं या नहीं। उत्पादन की अनुमानित लागत के संबंध में, आवेदक ने इस स्तर पर सत्यापन योग्य अंतरराष्ट्रीय कच्चे माल या उपयोगिता मूल्य प्रदान नहीं किए हैं। जहां तक किसी उपयुक्त तीसरे देश को निर्यात किए जाने पर समान वस्तु के तुलनीय प्रतिनिधि मूल्य का संबंध है, उस उद्देश्य के लिए उपलब्ध प्रकाशित स्रोत छह अंकों के स्तर पर व्यापार की रिपोर्ट करता है जो केवल

विषय वस्तुओं को कवर नहीं करता है। तदनुसार, इस स्तर पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए इनमें से किसी पर भी विचार नहीं किया गया है। दीक्षा के उद्देश्य से, जापान और कोरिया आरपी के संबंध में सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों पर निर्धारित किया गया है, भारत में इस तरह की वस्तु के उत्पादन की अनुकूलित लागत को उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के रूप में अपनाया गया है, विधिवत समायोजित किया गया है और उचित लाभ मार्जिन को जोड़ा गया है। शुरुआत के बाद, सामान्य मूल्य संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों की प्रतिक्रियाओं और ऐसे आगे के साक्ष्यों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा जिन्हें रिकॉर्ड पर रखा जा सकता है।

iii. निर्यात मूल्य

15. विचाराधीन उत्पाद का निर्यात मूल्य विचाराधीन उत्पाद के सीआईएफ मूल्य पर विचार करके निर्धारित किया गया है, जैसा कि डीजी सिस्टम्स लेनदेन वार आयात डेटा में रिपोर्ट किया गया है। आवेदक द्वारा किए गए दावे के अनुसार उचित समायोजन पर समुद्री माल ढुलाई, समुद्री बीमा, बंदरगाह व्यय, इन्वेंट्री ले जाने की लागत और ऋण लागत के कारण एक्स-फैक्ट्री निर्यात मूल्य पर पहुंचने पर विचार किया गया है।

iv. डंपिंग मार्जिन

16. सामान्य मूल्य और ऊपर बताए गए अनुसार निर्धारित निर्यात मूल्य के आधार पर, डंपिंग माजन क्या है? प्रथम दृष्टया प्रत्येक विषय देश के लिए सकारात्मक और महत्वपूर्ण, प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि विषय देशों से विषय वस्तुओं की डंपिंग जारी है।

ज. पाटन और क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना

17. आवेदक ने प्रदान किया है प्रथम दृष्टया घरेलू उद्योग को लगातार नुकसान का साक्ष्य। भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में विषय देशों से आयात की मात्रा में पूर्ण रूप से वृद्धि हुई है। संबंधित देशों से कीमत में कटौती सकारात्मक है, डंप किए गए आयात ने प्रथम दृष्टया आवेदक की कीमतों को कम कर दिया है, जो क्षति की अवधि के दौरान बिक्री की लागत से कम हो गया है, और विषय आयात का लैंडेड मूल्य घरेलू उद्योग के गैर-हानिकारक मूल्य से कम है। आवेदक ने इष्टतम क्षमता उपयोग से कम काम किया है, क्षति की अवधि में इसकी बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है, और इसे वित्तीय नुकसान, नकद हानि और क्षति की अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर नकारात्मक रिटर्न का सामना करना पड़ा है। आवेदक ने आगे दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में डंपिंग और क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना है, क्योंकि संबंधित देशों में उत्पादकों के पास महत्वपूर्ण उत्पादन क्षमता है, जो भारत में

मांग से कई गुना अधिक है, और चीन पीआर में और क्षमता विस्तार किया जा रहा है। इसने यह भी दावा किया है कि संबंधित देशों में उत्पादक निर्यातोन्मुखी हैं, और यह कि संबंधित देशों से तीसरे देशों को निर्यात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा घरेलू उद्योग के अनुमानित सामान्य मूल्य और गैर-हानिकारक मूल्य से कम कीमतों पर है, और भारत को निर्यात मूल्य से कम है। आवेदक द्वारा दी गई जानकारी *प्रथम दृष्टया* (ख) सरकार ने संबंधित देशों से पाटन की निरंतरता और पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के मामले में डंपिंग के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना और घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने की संभावना को दर्शाया है।

झ. सूर्यास्त समीक्षा जांच की शुरुआत

18. आवेदक द्वारा दायर विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर, और इसके आधार पर खुद को संतुष्ट करने के बाद, *प्रथम दृष्टया* आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य डंपिंग और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना की पुष्टि करते हैं, और नियमों के नियम 23(1बी) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 ए (5) के अनुसार, प्राधिकरण एतद्वारा विषय देशों में उत्पन्न होने वाली या निर्यात की जाने वाली विषय वस्तुओं के संबंध में लागू पाटनरोधीशुल्क के निरंतर अधिरोपन की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए एक सूर्यास्त समीक्षा जांच शुरू करता है, और यह जांचने के लिए कि क्या इस तरह के शुल्क की समाप्ति से डंपिंग की निरंतरता या पुनरावृत्ति होने की संभावना है और घरेलू उद्योग को क्षति लगने की संभावना है।

ञ. प्रक्रिया

19. सूर्यास्त समीक्षा जांच में अंतिम निष्कर्ष संख्या 14/36/2016-डीजीएडी दिनांक 13 दिसंबर 2017 के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा, जिसमें संबंधित देशों में उत्पन्न होने वाली या उनसे निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधीशुल्क लगाने की सिफारिश की गई है और अंतिम निष्कर्ष संख्या 7/26/2021-डीजीटीआर दिनांक 27 अगस्त 2021 ने पाटनरोधीशुल्क को जारी रखने की सिफारिश की है।
20. नियमों के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान इस समीक्षा में विभिन्न परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

ट. जानकारी प्रस्तुत करना

21. सभी इच्छुक पार्टियों को सेतु पोर्टल (<http://setu.dgtr.gov.in>) पर खुद को पंजीकृत करना आवश्यक है। इच्छुक पार्टियों के सभी संचार और सबमिशन उनके पंजीकृत नाम और संबंधित सेतु केस आईडी - एडी/एसएसआर/011/2026 के तहत सेतु पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सबमिशन का वर्णनात्मक भाग खोजने योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में है और डेटा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हैं।
22. संबंधित देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावासों के माध्यम से संबंधित देशों की सरकारों और भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं को इस विषय के सामान से संबंधित होने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे दी गई समय सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर सकें। ऐसी सभी जानकारी इस दीक्षा अधिसूचना, नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से दर्ज की जानी चाहिए।
23. कोई अन्य इच्छुक पक्ष भी वर्तमान जांच के लिए फॉर्म और तरीके से प्रासंगिक सबमिशन कर सकता है, और समय सीमा के भीतर, इस अधिसूचना में निर्धारित नियम, और प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए लागू व्यापार नोटिस। प्राधिकरण के समक्ष कोई भी गोपनीय सबमिशन करने वाले किसी भी पक्ष को अन्य इच्छुक पार्टियों को उसी का गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराना आवश्यक है।
24. इच्छुक पार्टियों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (<http://setu.dgtr.gov.in>) पर नियमित रूप से नजर रखें। इच्छुक पार्टियों को निर्देश दिया जाता है कि वे नियमित रूप से डीजीटीआर (<http://dgtr.gov.in/>) की वेबसाइट पर जाएं ताकि वे विषय की जांच में आगे के घटनाक्रमों से अवगत रहें और प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं और ऐसी अन्य जानकारी के संबंध में समय-समय पर जारी किए जा सकने वाले नोटिसों के बारे में सूचित रहें।

ठ. अंतिम तिथि

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी इच्छुक पार्टियों द्वारा अपने पंजीकृत नाम और संबंधित सेतु केस आईडी - AD/SSR/011/2026 के तहत SETU पोर्टल (<http://setu.dgtr.gov.in>) पर अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक सबमिशन के दोनों संस्करण, गोपनीय संस्करण (CV) और गैर-गोपनीय संस्करण (NCV), को सूचना पत्रों के प्रसारण की तारीख से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्दिष्ट कॉलम में अपलोड किया जाना चाहिए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, आवेदन का गैर-गोपनीय संस्करण और संबंधित प्रश्नावली शामिल है, जो ज्ञात इच्छुक पार्टियों और विषय देशों के राजनयिक प्रतिनिधि (ओं) को पाटनरोधीनियम, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त जानकारी अधूरी है, तो प्राधिकरण रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमों के अनुसार अपने निष्कर्ष रिकॉर्ड कर सकता है।
26. सभी इच्छुक पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (रुचि की प्रकृति सहित) को सूचित करें और केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं दाखिल करें।
27. पीयूसी/पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणी दर्ज करने के लिए 15 दिन की अवधि इस दीक्षा अधिसूचना के पैराग्राफ 25 में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।
28. पीयूसी/पीसीएन के संशोधन के कारण विस्तार: 15 दिनों तक समय का विस्तार दिया जाएगा यदि प्राधिकरण, बाद के नोटिस के माध्यम से, पीयूसी और पीसीएन को संशोधित करता है जो पहले प्रस्तावित नहीं था या दीक्षा अधिसूचना से अलग है। संशोधित पीयूसी और पीसीएन की ऐसी अधिसूचना की तारीख से 15 दिनों का विस्तार दिया जाएगा। इस पैराग्राफ में बताए गए 15 दिनों का समय विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होता है जहां जांच शुरू होने के बाद पीयूसी और पीसीएन पद्धति में कोई बदलाव नहीं होता है। 15 दिनों के विस्तार (यदि दी गई हो) से परे समय के और विस्तार के अनुरोधों पर आमतौर पर नियमों के नियम 6(4) के अनुरूप असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर विचार नहीं किया जाएगा।

29. विस्तार के लिए कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षों द्वारा मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद सबमिट किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ड. गोपनीय आधार पर जानकारी प्रस्तुत करना

30. जहां वर्तमान जांच का कोई पक्ष गोपनीय प्रस्तुतियाँ करता है या प्राधिकरण के समक्ष गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करता है, ऐसे पक्ष को नियमों के नियम 7(2) के संदर्भ में और इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी प्रासंगिक व्यापार नोटिसों के अनुसार ऐसी जानकारी का एक गैर-गोपनीय संस्करण एक साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन करने में विफलता के कारण प्रतिक्रिया/प्रस्तुतियाँ अस्वीकृत हो सकती हैं।
31. प्रश्नावली के उत्तरों सहित प्राधिकरण के समक्ष कोई भी प्रस्तुतीकरण (परिशिष्ट/अनुलग्नक सहित) करने वाले पक्षों को गोपनीय और गैर-गोपनीय संस्करण अलग-अलग दाखिल करने की आवश्यकता होती है।
32. इस तरह के सबमिशन को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से 'गोपनीय' या 'गैर-गोपनीय' के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए। इस तरह के चिह्नों के बिना प्राधिकरण को किए गए किसी भी सबमिशन को प्राधिकरण द्वारा 'गैर-गोपनीय' जानकारी के रूप में माना जाएगा, और प्राधिकरण अन्य इच्छुक पार्टियों को इस तरह के सबमिशन का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।
33. गोपनीय संस्करण में वह सभी जानकारी शामिल होगी जो प्रकृति से, गोपनीय और/या अन्य जानकारी है, जिसे ऐसी जानकारी का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। उस जानकारी के लिए जो प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया जाता है, या वह जानकारी जिस पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, जानकारी के आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई जानकारी के साथ एक अच्छा कारण विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।
34. इच्छुक पार्टियों द्वारा दायर की गई जानकारी का गैर-गोपनीय संस्करण गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी अधिमानतः अनुक्रमित या खाली कर दी गई हो (जहां इंडेक्सेशन संभव नहीं है) और ऐसी जानकारी को उस जानकारी के

आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से सारांशित किया जाना चाहिए जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है।

35. गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई जानकारी के सार की उचित समझ की अनुमति देने के लिए गैर-गोपनीय सारांश पर्याप्त विवरण में होना चाहिए। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्ष यह संकेत दे सकता है कि ऐसी जानकारी सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, और नियमों के नियम 7 के संदर्भ में पर्याप्त और पर्याप्त स्पष्टीकरण वाले कारणों का एक विवरण, और प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए उपयुक्त व्यापार नोटिस, कि ऐसा सारांश संभव क्यों नहीं है, प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।
36. इच्छुक पार्टियां दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रचलन की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकती हैं।
37. इसके सार्थक गैर-गोपनीय संस्करण या नियमों के नियम 7 के संदर्भ में पर्याप्त और पर्याप्त कारण विवरण के बिना किया गया कोई भी सबमिशन, और गोपनीयता के दावे पर प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए उपयुक्त व्यापार नोटिस को प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।
38. प्राधिकरण प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध की आवश्यकता नहीं है या यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकता है।
39. प्राधिकरण संतुष्ट होने और प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार करने पर, ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना किसी भी पक्ष को इसका खुलासा नहीं करेगा।

ढ. सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण

40. किसी भी इच्छुक पार्टी द्वारा किए गए सबमिशन के सभी गैर-गोपनीय संस्करण अन्य इच्छुक पार्टियों के लिए सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से सुलभ होंगे।

ण. असहयोग

41. यदि कोई इच्छुक पक्ष इस आरंभिक अधिसूचना में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित उचित अवधि के भीतर या निर्धारित समय के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान करने से इनकार करता है और अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकरण ऐसे इच्छुक पक्ष को गैर-सहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है जो वह उचित समझे।

Digitally signed by
Amitabh Kumar
Date: 30-09-2026
13:36:25
(अमिताभ कुमार)
नामित प्राधिकारी